उत्तम गुणवत्ता को कोयले का अभाव है और उसका आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त किस्म के कोयले की आवश्यकता को देखते हुए उसका कितनी मात्रा में आयात किया जाता हैं;

(ग) क्या यह सच हैं कि उक्त कोयले के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उसका आयात बन्द करने हेतु कोयला-घोवलशालायें स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में अप्रैल, 1993 तक कोयला –घोवलशालाओं की उत्पादन क्षमता कितनी थी और इसमें से निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की अलग-अलग क्षमता कितनी थी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) इस्पात संयंत्रों में प्रयोग किए जाने के लिये निम्न राखीय तत्व वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले धातु कर्मीय किस्म के कोककर कोयल की कमी हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान इस्पात कंपियों द्वारा लगभग 8.47 मिलियन टन करेककर कोयले का आयात किया गया हैं, अर्थात् भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) और टाटा आयरण एंड स्टील कम्पनी (टिस्को)

(ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड स्व-निर्मित, स्व-चालित आधार पर कोयला वाशरियों की स्थापना किये जाने के लिये विश्वव्यापी स्तर पर विदेशी तथा भारतीय पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। इस योजना के तहत पार्टियों को स्वयं निवेश, डिजाइन, स्थापना कार्यचालन, अनुरक्षण और संयंत्र का स्वामित्व रखना होगा। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संयंत्र के लिये पट्टे पर भूमि मुहैया किया जाना, विद्युत का निर्माण तथा भारित आधार पर निर्माण किया जाना अपेक्षित हैं। सामान्य शर्ते निम्न रूप में हैं:-

(i) निवेशकर्त्ता को स्वयं वित्त, निर्माण करने, कार्यचालन की , अनुरक्षण की तथा संयंत्र को अपने स्वामित्व में रखना होगा।

(ii) कच्चा कोयला एवं घुले हुये उत्पाद को.इ.लि. की संपत्ति होगी और घुले हुये उत्पादनों का विपणन को.इ.लि. द्वारा किया जायेगा।

(iii) कच्चे कोयले एवं धुले हुये उत्पादनों के मानदण्ड जिसमें प्रतिशत अधिप्राप्ति शामिल हैं, निर्धारित किये जायेंगे।

(iv) उचित परिवर्तित लागत, जिसमें धुले कोयले के प्रति टन उचित कर की अधिप्राप्ति शामिल हैं, का सफल निवेशकर्त्ता को भुगतान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रेषण से पहले कोयले की धुलाई के लिये उपभोक्ता कोयले का उत्पादन किए जाने वाले के नजदीक वाशरियों की स्थापना कर सकते हैं।

अप्रैल, 1995 के अन्त में नीचे दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार 19 कोककर कोयला वाशारियां कार्य कर रही थी

कंपनी	वाशरियों की संख्या	संचलन-योग्य क्षमता (मि.ट.प्र.व.)
कोल इंडिया लिमिटेड	15	25.22
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	2	3.00
टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी	2	3.94
कुल जोड:	19	32.16

आठवी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों की समीक्षा

101. **श्री इकबाल सिंह** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों की समीक्षा करने हेतु कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उसमें किन-किन मुद्दों की समीक्षा की गई तथा क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) आठवी योजना की मध्यावधि मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रक्रिया भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से योजना आयोग में चल

रही हैं। पूर्ण योजना आयोग की बैठक आयोजित करने का प्रश्न मध्यावधि मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही उठेगा।

बाल श्रम का उन्मूलन

102. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या 15 अगस्त, 1994 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिये एक घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश से बाल श्रम का उन्मूलन करने में सफल हो पाई हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1995 के "संडे आब्जर्वर" के "रूपीज 850 करोड़ फार इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर अनयूटीलाइज्ड फार लैक आफ प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) जी, हां। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 1994 को लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की थी कि अगले 4.5 वर्षो में जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए 20 लाख बच्चोंके कार्य से हटाया जाएगा और उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण (एन.ए.ई.सी.एल.) का गठन किया गया हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने "बाल श्रमिकों की पहचान करने, उन्हे मुक्त कराने और पुनर्वासित करने" के संबंध में एक परिपत्र अपनाया हैं। इस परिपत्र को माननीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही अग्रेषित कर दिया गया हैं। इस परिपत्र में विशेष कर के जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सभी प्रकार की अपेक्षित कार्रवाई शामिल की गई हैं। संक्षेप में,

इसके तहत बाल श्रम उन्मूलन संबंध प्रयास को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं और योजनाओं को कार्यान्वयन स्तर- जिला स्तर पर अभिसारित करने की अपेक्षा की गई हैं।

(घ) जी, हां।

(ड.) और (च) प्रस्ताव हैं कि सन् 2000 तक 20 लाख बाल श्रमिकों का जोखिमकारी व्यवसायो से उन्मूलन किया जाएगा। अनुमान हैं कि इस प्रयोजन के लिए 850 करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता होगी। कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वर्ष हेतु 34.4 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई हैं। नई दिल्ली में बाल श्रम को सर्वोच्च घटनाओं वाले 100 जिलाधीशों को एक कार्यशाला 13-14 सितम्बर, 1995 को आयोजित की जानी हैं। संबंधित जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के आधार पर अपने-अपने जिलों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करे। इस योजना के अन्तर्गत कार्य से हटाए गए बालकों को विशेष स्कूलों के माध्यम से प्राइमरी स्तर की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणहार और वृत्तिकाएं प्रदान की जाएगी।

असंगठित क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसरो में वृद्वि

103. **श्री राम जेठमलानी**:

श्री सुषमा स्वराज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1995 से दैनिक "हिन्दुस्तान" में "अनओरगेनाइज्ड सैक्टर्स कन्ट्रीब्यूट मोर टू एक्पलोयमेंट ग्रोथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने की अधिक क्षमता हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(घ) क्या यह भी सच हैं कि असंगठित क्षेत्र में आमश्रमिक की स्थिति दयनीय भी हैं; और

(ड.) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) असंगठित-क्षेत्र, जिसमें अन्यों के साथ-साथ कृषिय और निर्माण क्रियाकलाप शामिल हैं, में कुल